बिना शौचालय न लड़ पाएंगे चुनाव

पंचायत व नगर निकाय चुनाव के लिए शर्त

जागरण ब्यूरो, पटना : अपने घर में शौचालय नहीं बनाने वाला व्यक्ति पंचायत व नगर निकायों का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मंगलवार को विश्व शौचालय दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए पंचायत व नगर निकाय चुनाव से संबंधित कानून में संशोधन किया जाएगा। शौचालय निर्माण के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने की अधिकारियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हर पंचायत में दो लाख की राशि का एक 'ब्रिज फंड' उपलब्ध रहेगा।

विश्व शौचालय दिवस पर 'मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के अभिशरण' विषय पर श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव अभी दूर है। लेकिन, अभी से अपने-अपने घरों में शौचालय बनवा लें। लाभान्वितों द्वारा शौचालय बना लेने के बाद ही निर्मल भारत अभियान के तहत उन्हें इसका 4600 रुपये मिलने का प्रावधान है। यह एक समस्या है, जिसके समाधान के लिए राज्य सरकार हर पंचायत में 'ब्रिज फंड' बनाएगी जिससे निर्माण के दौरान ही लाभुक को 4600 रुपये मिल जाएंगे। केंद्र सरकार से यह राशि मिलने पर ब्रिज फंड में जमा हो जाएगी। इस तरह पैसे के कारण काम नहीं रुकेगा। केंद्र सरकार 1.11 करोड़ बीपीएल ■शेष पृष्ठ 15 पर

विश्व शौचालय दिवस पर मुख्यमंत्री का एलान

- बोले नीतीश-इसके लिए बदलेगा पंचायत चुनाव संबंधी कानून
- शौचालय निर्माण के लिए हर पंचायत में रहेगा ब्रिज फंड
- केंद्र सरकार 2.19 करोड़ बीपीएल परिवार के लिए राशि दे

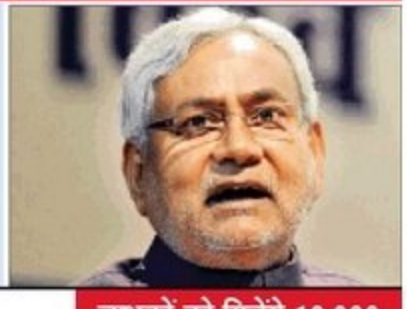

इस साल 15 लाख का लक्ष्य

- इस वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास के 7.32 लाख लाभान्वित तथा हर ग्राम पंचायत में 100 की दर से 8.40 लाख यानि करीब 15 लाख का लक्ष्य।
- महादलित वर्ग के लाभान्वितों के लिए राज्य सरकार उनके हिस्से की 900 रुपये की राशि खुद वहन करेगी। पहले यह राशि 300 रुपये थी। अगले वित्तीय वर्ष में 20 लाख का लक्ष्य है। 2022 तक शत-प्रतिशत कवरेज।

लाभुकों को मिलेंगे 10,000

निर्मल भारत अभियान से	4600 रु.
इंदिरा आवास से	4500 रु.
अपना अंशदान	900 रु.

बिहार से निकला 'पहले शौचालय-फिर देवालय' का नारा

जागरण ब्यूरो, पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर प्रहार किया। कहा कि अभी 'पहले शौचालय -फिर देवालय' का नारा दिया जा रहा है। हमने तो 2007 में ही यह नारा दिया। प्रदेश में गांवों में दीवारों पर यह लिखा नजर आएगा। 2009 में जब मैंने विकास यात्रा शुरु की तो लोगों ने दिन में मशाल जलाकर शौचालय बनाने का संकल्प लिया। बाद की हर यात्रा में भी ऐसे ही संकल्प लिए गए। मुख्यमंत्री के अनुसार यह बात भी लोगों के दिलों में बैठी कि जिस घर में शौचालय नहीं होगा, ■शेष पृष्ठ 15 पर

प्रथम पृष्ठ का शेष

बिना शौचालय न लड़ पाएंगे चुनाव

परिवार के लिए राशि देती है, जबकि राज्य के अपने पारिवारिक सर्वे के अनुसार बीपीएल परिवार की संख्या 2.19 करोड़ है। केंद्र सरकार 2.19 करोड़ के हिसाब से हमें राशि दे। इस अभियान के तहत बीपीएल एवं एपीएल, दोनों ही श्रेणी के परिवारों को कवर किया जाना है। 2015 तक निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत पूरा कर लेना है। उन्होंने कहा- मेरी अधिकारियों से अपील है कि यह काम समय से पहले ही पूरा कर लें। मानव विकास मिशन के माध्यम से मैं खुद अभियान की समीक्षा करुंगा। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि खुले में शौच से अधिक अपमानजनक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। आरंभ में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने अभियान के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अंजनी कुमार सिंह, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव एसएम राजू, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख जेएस चौधरी आदि भी मौजूद थे।